जलवायु विकास को चाहिए निजी निवेश : विश्व बैंक

भारत की शहरी आबादी 2070 तक पहुंचेगी 1.1 अरब

शहरों के जलवायु अनुकूल विकास में निजी निवेश केवल 5%

नयी दिल्ली, 22 जुलाई (वार्ता) विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत की शहरी आबादी अगले 25 वर्षों में दोगुनी होकर 95.1 करोड़ और वर्ष 2070 तक 1.1 अरब तक पहुंच जाएगी. इस तीव्र शहरीकरण के साथ, इन शहरों के जलवायु अनुकूल विकास के लिए वर्ष 2070 तक लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर के भारी निवेश की आवश्यकता होगी, जिसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना अनिवार्य है.

विश्व बैंक ने मंगलवार को भारत में मजबूत और समृद्ध शहरों की ओर% नामक एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें शहरी बाढ़ और बढ़ते तापमान जैसी जलवायु तथा बुनियादी ढाँचे से जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा की गई है. विश्व बैंक के भारत में निदेशक ओगुस्ते क्वामे ने बताया कि शहरों में बाढ़ और लू की घटनाएँ बढ़ रही हैं, और इन्हें मौसमी परिस्थितियों के लिए मजबूत बनाना आवश्यक है. उन्होंने चिंता व्यक्त की कि देश में शहरों को जलवायु अनुकूल बनाने की दिशा में बुनियादी ढाँचे में निजी क्षेत्र का निवेश केवल पाँच प्रतिशत है, जिसे काफी बढ़ाने की जरूरत है.

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और समाधान– रिपोर्ट के अनुसार, 1985 से 2015 के दौरान 10 बड़े भारतीय शहरों में तापमान में चिंताजनक वृद्धि के मामले 71 प्रतिशत बढ़ गए. चेन्नई, सूरत और लखनऊ जैसे शहरों में रात का तापमान आसपास के गैर-शहरी इलाकों की तुलना में 3-5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है, जिसका मुख्य कारण कंक्रीट के ढाँचों में बेतहाशा वृद्धि है. वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2050 तक गर्मी से संबंधित मौतों के मामले दोगुने से भी अधिक होकर 3,28,500 तक पहुँचने का अनुमान है.

निजी क्षेत्र की भूमिका और सरकारी पहल

क्वामे ने जोर दिया कि सरकार अकेले इस विशाल कार्य को पूरा नहीं कर सकती. इसके लिए निजी-सरकारी सहभागिता या अन्य मॉडल अपनाए जा सकते हैं, जिसमें निजी कंपनियों को इक्विटी और ऋण देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है, और शहरी निकाय भी अपने स्तर पर पूँजी जुटा सकते हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार स्वयं इस दिशा में पहल कर रही है, जिसमें नए हब शहरों का विकास (जैसे अमरावती) और मौजूदा शहरों (जैसे दिल्ली-मुंबई) में रचनात्मक बदलाव शामिल हैं.

स्मार्टफोन बाजार में 7% की छलांग : रिपोर्ट

अप्रैल-जून 2025 में 3.9 करोड़ यूनिट्स की बिक्री, वीवो टॉप पर

नई दिल्ली, 22 जुलाई. भारत का स्मार्टफोन बाजार अप्रैल-जून 2025 की अवधि में 7 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 3.9 करोड़ यूनिट्स पर पहुंच गया है. यह वृद्धि इन्वेंट्री की चुनौतियों में कमी और विक्रेताओं के नए सिरे से सक्रिय होने के कारण हुई है, जैसा कि एक नई रिपोर्ट में बताया गया है.

कैनालिस की रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि मुख्य रूप से दूसरी तिमाही में हुए नए लॉन्च के कारण संभव हुई, क्योंकि पिछली तिमाही में उच्च इन्वेंट्री स्तरों के कारण विक्रेताओं ने नए उत्पाद लॉन्च करने में देरी की थी. कैनालिस के प्रमुख विश्लेषक संयम चौरसिया ने कहा कि शीर्ष पांच से आगे बढ़ती प्रतिस्पर्धा भारतीय स्मार्टफोन परिदृश्य को नया रूप दे रही है, क्योंकि प्रीमियम ब्रांड और डिजाइन-आधारित कंपनियां अपनी रणनीति में सुधार कर रही हैं.

अप्रैल-जून तिमाही में वीवो (आईक्यूओओ को छोड़कर) 81 लाख यूनिट्स की शिपमेंट और 21 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ स्मार्टफोन सेगमेंट में सबसे आगे रहा. सैमसंग 62 लाख यूनिट्स और 16 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा. ओप्पो (वनप्लस को छोड़कर) 50 लाख यूनिट्स के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया, और श्याओमी ने भी 50 लाख यूनिट्स की शिपिंग की. रियलमी 36 लाख यूनिट्स के साथ शीर्ष पांच में शामिल रहा.

पीएलआई योजनाओं से 1.76 लाख करोड़ का निवेश : सरकार

मार्च 2025 तक 14 सेक्टरों में रु. 1.76 लाख करोड़ का निवेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई. संसद में मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मार्च 2025 तक 14 सेक्टरों में 1.76 लाख करोड़ का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है.

इसके परिणामस्वरूप ?16.5 लाख करोड़ से अधिक का उत्पादन/बिक्री में वृद्धि हुई है और 12 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि 14 सेक्टरों में PLI योजनाओं के तहत अब तक 806 आवेदनों को मंजूरी दी गई है. इन योजनाओं ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित कर उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा दिया है. प्रमुख सेक्टरों का प्रदर्शन- फार्मास्यूटिकल्स- इस सेक्टर ने योजना के पहले तीन वर्षों में 2.66 लाख करोड़ की संचयी बिक्री हासिल की है, जिसमें 1.70 लाख करोड़ का निर्यात शामिल है. इस योजना ने भारत को थोक दवाओं का शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बनने में योगदान दिया है. मेडिकल डिवाइस- पीएलआई योजना के तहत, 21 प्रोजेक्ट्स ने 54 अद्वितीय मेडिकल डिवाइस का निर्माण शुरू कर दिया है, जिनमें लीनियर एक्सेलेरेटर, एमआरआई, सीटी-स्कैन, स्टेंट, डायलाइजर मशीन जैसे हाई-एंड डिवाइस शामिल हैं.

21,534 करोड़ की संचयी प्रोत्साहन राशि वितरित की गई

राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि 24 जून 2025 तक 12 सेक्टरों के लिए रुपए 21,534 करोड़ की संचयी प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है. इन सेक्टरों में लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हार्डवेयर, थोक दवाएं, मेडिकल डिवाइस, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट, खाद्य प्रसंस्करण, व्हाइट गुड्स, ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स, स्पेशियलिटी स्टील, कपड़ा उत्पाद और ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट्स शामिल हैं.

2026 में भारत की विकास दर होगी 6.6 प्रतिशत

स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिपोर्ट में 2026 में 6.6% विकास का अनुमान

वित्त वर्ष 2025 में ग्रोथ 6.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद

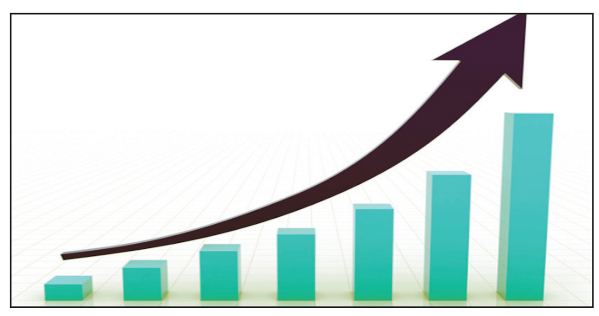

नई दिल्ली, 22 जुलाई. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की मंगलवार को जारी वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का आर्थिक विकास वित्त वर्ष 2026 में 6.6 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2025 के 6.5 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है.

यह वृद्धि मुख्य रूप से बेहतर खपत मांग, हालिया मौद्रिक नीति में नरमी, आयकर में कटौती, अच्छे मानसून और कच्चे तेल की कीमतों में कमी की संभावना से समर्थित होगी.रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत मैक्रो फंडामेंटल भारत को स्थिरता प्रदान करते हैं, हालांकि बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत टैरिफ जोखिमों से अछूता नहीं है. अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ताओं का परिणाम भारत की विकास संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा.

वैश्विक परिदृश्य और भारत का लचीलापन– यह सकारात्मक दृष्टिकोण ऐसे समय में आया है जब बैंक ने व्यापार नीति की अनिश्चितता के बीच 2025 के लिए अपने वैश्विक विकास पूर्वानुमान को थोड़ा कम करके 3.1 प्रतिशत कर दिया है. भारत आर्थिक अनुसंधान की प्रमुख अनुभूति सहाय ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक क्रय शक्ति में सुधार की उम्मीद जताई है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि शहरी मांग को प्रतिचक्रीय उपायों से समर्थन मिलने की उम्मीद है, लेकिन शहरी परिवार कम दरों और कर कटौती के लाभों का आंशिक रूप से उपयोग कर्ज चुकाने और बचत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं.

राजकोषीय घाटा और रेटिंग

सहाय ने बताया कि सकल घरेलू उत्पाद के 7 प्रतिशत से नीचे संयुक्त राजकोषीय घाटा सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है, जैसा कि 2024 में भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को सकारात्मक में अपग्रेड करते समय एस एंड पी ने उजागर किया था. वित्त वर्ष 2026 पहला वर्ष होगा जब संयुक्त राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 7 प्रतिशत से नीचे रहेगा, और मध्यम अवधि में भी इसके 7 प्रतिशत से नीचे रहने की उच्च संभावना है.

इटरनल के शानदार नतीजों से शेयर 10 प्रतिशत उछला

सेंसेक्स दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद 13 अंकों की गिरावट के साथ बंद

निफ्टी 30 अंकों की हल्की गिरावट के साथ 25,060.90 पर बंद हुआ

मुंबई, 22 जुलाई (वार्ता). घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को शुरुआती तेजी के बाद बिकवाली हावी हो गयी और सीमित कारोबार के बीच प्रमुख सूचकांकों में हल्की गिरावट दर्ज की गयी. हालांकि अच्छे तिमाही परिणाम के दम पर सेंसेक्स में शामिल इटरनल का शेयर 10 प्रतिशत की जोरदार उछाल के साथ बंद हुआ.

सुबह के सत्र में पिछले कारोबारी दिवस की तेजी को बरकरार रखते हुये बीएसई का सेंसेक्स 327.09 अंक की तेजी के साथ 82,527.43 अंक पर खुला और 82,538.17 अंक तक पहुंच गया. लेकिन इसके बाद बाजार में बिकवाली शुरू हो गयी और दोपहर के करीब सेंसेक्स 82,110.63 अंक तक उतर गया था. अंत में यह 13.53 अंक यानी 0.02 प्रतिशत की हल्की गिरावट में बंद हुआ.

निफ्टी-50 भी 75.95 अंक की बढ़त में 25,166.65 अंक पर खुला और ऊपर 25,182 अंक को छूने के बाद 25,035.55 अंक तक उतर गया. कारोबार की समाप्ति पर यह 29.80 अंक यानी 0.12 फीसदी की नाम मात्र की गिरावट के साथ 25,060.90 अंक पर रहा एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे ने बताया कि निफ्टी पर दबाव बना रहेगा.

वित्तीय समावेश सूचकांक 4.3 प्रतिशत बढ़कर 67 पर पहुंचा

मुंबई, 22 जुलाई. भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष में उसका वित्तीय समावेश सूचकांक (FI-सूचकांक) 4.3 प्रतिशत बढ़कर 67 पर पहुंच गया है. यह देश में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की स्थिति में लगातार सुधार को दर्शाता है, जो मार्च 2024 में 64.2 था.

केंद्रीय बैंक ने बताया कि पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता सहित सभी उप-सूचकांकों में वृद्धि दर्ज की गई. यह वृद्धि वित्तीय समावेश के दायरे में अधिक लोगों को लाने और वित्तीय साक्षरता के प्रयासों का परिणाम है.

FI-सूचकांक एक व्यापक माप है, जिसमें बैंक, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र शामिल हैं.

दिल्ली की ईवी नीति 31 मार्च 2026 तक बढ़ी

नई दिल्ली, 22 जुलाई. दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है. परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार को बताया कि नई नीति के मसौदे पर लोगों से सुझाव लेने में लगने वाले समय के कारण यह विस्तार किया गया है. मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.सिंह ने कहा कि यह विस्तार नागरिकों, उद्योग विशेषज्ञों और पर्यावरण समूहों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया गया है.

इस विस्तारित अवधि के दौरान, ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सब्सिडी और छूट की समीक्षा करने, सुरक्षित ई-कचरे और बैटरी निपटान की व्यवस्था विकसित करने, तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों की भूमिका को परिभाषित करने जैसे प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी.वर्तमान ईवी नीति को पहली बार 2020 में पेश किया गया था, और अगस्त 2023 में इसकी अवधि समाप्त होने के बाद से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सुचित किया जाता है पूर्व में मेरा नाम नरेश कुमार नगपुरे था।
जिसे बदलकर नरेश नगपुरे कर दिया है। मुझे नरेश नगपुरे पिता गंगाराम नगपुरे नाम से जाना पहचाना जाऐं।
सही
नरेश नगपुरे
बोदा, वार्ड नं– 8, बालाघाट

नाम परिवर्तन

मैं विभोर अग्रवाल आत्मज श्री ललित कुमार अग्रवाल, आयु वयस्क, निवासी LIG - 21, नेहरू नगर, पुलिस मैदान के पास, भोपाल शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि पहले मुझे विभोर आत्मज श्री ललित कुमार के नाम से जाना जाता था. यह कि मेरे सभी दस्तावेजों में विभोर अग्रवाल आत्मज श्री ललित कुमार अग्रवाल दर्ज है. आज के बाद मुझे विभोर अग्रवाल आत्मज श्री ललित कुमार अग्रवाल के नाम से जाना एवं पहचाना जाए.

विभोर अग्रवाल आत्मज
श्री ललित कुमार अग्रवाल

प्रीमियम संपत्तियों का बढ़ता दबदबा : रिपोर्ट

2025 की पहली छमाही में रु.1 करोड़ से अधिक के घरों की बिक्री 62प्रतिशत

नई दिल्ली, 22 जुलाई. भारत के आवास बाजार में प्रीमियम संपत्तियों की ओर एक मजबूत रुझान देखने को मिल रहा है. मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में कुल आवासीय बिक्री का 62 प्रतिशत ?1 करोड़ से अधिक कीमत वाले घरों से दर्ज किया गया.

यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 51 प्रतिशत की तुलना में शानदार वृद्धि दर्शाता है, जो हाई-एंड हाउसिंग के लिए खरीदारों की बढ़ती पसंद का संकेत है.

जेएलएल द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, ?3-5 करोड़ की रेंज वाले घरों की मांग में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि रु. 5 करोड़ से अधिक कीमत वाले घरों में 2024 की पहली छमाही की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई. इस रुझान का असर नई परियोजनाओं के शुभारंभ पर भी पड़ा है; 2025 की पहली छमाही में, ?1 करोड़ से अधिक कीमत वाले घरों की संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो गई.

अकेले 2025 की दूसरी तिमाही में, भारत के शीर्ष सात शहरों में लगभग 70,000 घर बेचे गए, जो पिछली तिमाही की तुलना में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

[See Regulation 35(1)]

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR
2nd & 3rd Floor, Sanchar Vikas Bhavan (BSNL Building),
Near Head Post Office Residency Road, Jabalpur-482001, MP,
RC/502/2020

NOTICE TO SHOW CAUSE WHY A WARRANT OF ARREST SHOULD NOT BE ISSUED
[UNDER RULE 73 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH SECTION, 29 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993]

BANK OF BARODA
Versus
SHRI JITENDRA SAHANI

To
(CD1)SHRI JITENDRA SAHANI
HOUSE NO.-182, GUPTA COLONY, ANAND NAGAR, RAISEN ROAD, BHOPAL, M.P.-462022-462001
(CD2) M/S BALAJI CONSTRUCTION AND DEVELOPERS
D-12, PATEL NAGAR, RAISEN ROAD, BHOPAL, M.P.-462022
(CD3) MR RAJESH CHOURASIA S/O SHRI GOTIRAM CHOURASIA
HOUSE NO.-45, BIJLI COLONY, ANAND NAGAR, RAISEN ROAD BHOPAL, M.P.-462022

Whereas you have failed to pay the amount of arrears specified in the **OA/1490/2019** drawn up by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR for recovery of **Rs. 2047046.34 (Rupees Twenty Lakhs Forty Seven Thousands Forty Six And Paise Thirty Four Only)** along with interest plus cost payable by you as per certificate and it is proposed to execute the above Certificate by Arrest and Imprisonment of your persons.

You are hereby required to appear before the undersigned on **09/09/2025** and to show cause why you should not be arrested and committed to the CIVIL PRISON in execution of the said Certificate.

Given under my HAND and the SEAL of the Tribunal, on this date: **14/07/2025.**

Seal

Ms. Priti Desai
Recovery Officer-II
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED

SMFG IndiaCredit — Pragati Ki Nayi Pehchaan

कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के परंतुक के साथ पठित। इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका कब्जा **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड**/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित तिथि और समय पर **"जहां है जैसी है", "जो है जैसी है"** और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि नीचे उल्लिखित बकाया राशि और वसूली की तिथि तक उन पर आगे ब्याज और अन्य व्यय, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार को उल्लिखित उधारकताओं और जमानतदार(ओं) से देय हो। आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा (ईएमडी) और ईएमडी जमा की अंतिम तिथि भी नीचे दी गई हैः

उधारकर्ता/गारंटर/ऋण खाता	मांग सूचना की तिथि, राशि और कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य, ईएमडी और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि और समय
1. वंशिका इलेक्ट्रिकल 2. अमित राठौड़ 3. आरती राठौड़ लैन नंबर-213020911481965	13 फरवरी, 2024. रु. 52,16,695/- [बावन लाख सोलह हजार छह सौ पिनचानवे रुपये मात्र] भौतिक कब्जा 22-08-23	आरक्षित मूल्यः रु. 3560655 (केवल पैंतीस लाख साठ हजार छह सौ पचपन रुपये) ईएमडी रु. 356065.5/- (केवल तीन लाख छप्पन हजार पैंसठ रुपये और पांच पॉइंट) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 11/08/2025	दिनांकः12.8.2025 समयः सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

अचल संपत्ति का विवरणः वह समस्त संपत्ति टुकड़ा और पार्सल नजूल शीट संख्या 112 ब्लॉक संख्या 2 प्लॉट संख्या 48 क्षेत्रफल 39.75 27 = 1073.31 वर्ग फीट (99.75 वर्ग मीटर) वार्ड संख्या 15 राजोरिया मोहल्ला गंज सीहोर तहसील सीहोर और जिला सीहोर (म.प्र.) में स्थित है जो निम्नानुसार सीमाओं से घिरा हैः पूर्व-रोड निस्तारी, पश्चिम-रोड निस्तारी, उत्तर-अन्य का घर, दक्षिण-सुखराम का घर।

बिक्री की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें 1) श्री फ्रांसिस रोजारियो एम. +91 8655424523 2) श्री अमोल संभूस - +91 99798 89076 3) श्री पिंकेश पटेल +91 86557675324) श्री वीरेंद्र सिंह चुंडावत +919727760153 और बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.smfgindiacredit.com पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें

दिनांकः 23/07/2025
स्थानः सीहोर

एसडी/-, प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

हर चुनाव में पलटता है सियासी खेल

पटना. बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित चिरैया विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही चुनावी हलचलों का गवाह रहा है. यह क्षेत्र ना केवल अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां के चुनावी परिणाम भी हमेशा दिलचस्प होते हैं.

चिरैया विधानसभा क्षेत्र में राजनीति एक रोमांचक खेल की तरह होती है, जिसमें हर चुनाव के बाद परिणाम कभी भी बदल सकते हैं. चिरैया विधानसभा में सवर्ण, पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों का वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हर चुनाव के साथ नए समीकरण बनते हैं. यही वजह इस क्षेत्र को राजनीति का एक दिलचस्प रणक्षेत्र बनाता है.

चिरैया विधानसभा क्षेत्र बिहार के प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में से एक है. यह पूर्वी चंपारण जिले का हिस्सा है और इसका लोकसभा क्षेत्र भी पूर्वी चंपारण है. यह क्षेत्र सामाजिक और जातिगत दृष्टि से विविधतापूर्ण है, जहां यादव, भूमिहार, राजपूत, मुसलमान और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

यहां की राजनीति में सवर्ण, पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण अक्सर चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं. चिरैया विधानसभा में चुनावी मैदान में भाजपा, राजद, जदयू और कई अन्य छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते हैं.

इस विधानसभा क्षेत्र में वोटों का अंतर कभी बड़ा होता है तो कभी बेहद कम. 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने जीत दर्ज की.

भाजपा में युवाओं को आगे लाने की बड़ी तैयारी

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. सीट शेयरिंग उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर खींचातानी तो है ही, साथ ही अब युवा आबादी वाले राज्य में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी बड़ी तैयारी चल रही है. एक ओर जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव युवाओं को आगे करते नजर आते हैं, वहीं अब भाजपा के अंदर भी युवाओं को मौका देने और युवाओं को आगे लाने की बड़ी तैयारी चल रही है. ऐसे में विधानसभा चुनाव में कई नेताओं का टिकट उनके अधिक उम्र के कारण कट सकता है, जिससे नेताओं की टेंशन बढ़ गई है. साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है.

पश्चिम मध्य रेल

म.रे.प्र./कार्य/भोपाल ■ खुली ई-निविदा सूचना ■ दि. 21.07.2025

वरिष्ठ मण्डल अभियंता/सम./पश्चिम मध्य रेल, भोपाल, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए उनके समक्ष दर्शाई गई दिनांक को 15.30 बजे तक ई–टेन्डर आमंत्रित करते है। संपुर्ण निविदा प्रपत्र तथा निविदा से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी वेबसाईट **http://www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है एवं मण्डल रेल प्रबंधक (कार्य), पश्चिम मध्य रेल, भोपाल के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है। इस टेन्डर के लिए कोई मॅन्युअल ऑफर मान्य नहीं है। इस निविदा में कोई आवश्यक संशोधन, यदि जरुरी हो, तो निविदा खुलने के पूर्व वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा, तथा मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा। जिसे टेन्डर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है। निविदाकारों से निवेदन है, कि वह जीएसटी कानुन 2017 के प्रावधानों के अनुसार अपने दर तथा निविदाएं प्रस्तुत करें। **NIT No.:** 25-26-HQ-10-48, Date 16.07.2025. **Name of work including Location: हबीबगंज - डीआरएम कार्यालय में लेखा कार्यालय अनुभाग का नवीनीकरण और डिजिटलीकरण। Published cost of tender:** ₹ 46,05,351.24. **Earnest Money:** ₹ 92,100/-. **Completion Period:** 6 माह। **Last date for submitting tender:** 08.08.2025. **NIT No.:** 25-26-HQ-11-49, Date 17.07.2025. **Name of work including Location: भाग-अ) हबीबगंज - विद्युत सामान्य अनुभाग डीआरएम कार्यालय हबीबगंज भोपाल के कार्यालय में वर्क स्टेशन का नवीनीकरण एवं प्रावधान। भाग-ब) हबीबगंज के लिए क्यूबिकल (24" x 22") - एटीसी एचबीजे के परिसर में कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण/ऑनलाइन प्रशिक्षण सह सीबीटी सुविधा। Published cost of tender:** ₹ 25,51,755.99. **Earnest Money:** ₹ 51,000/-. **Completion Period:** 3 माह। **Last date for submitting tender:** 08.08.2025. **NIT No.:** 25-26-HQ-12-50, Date 19.07.2025. **Name of work including Location: भाग-ए) भोपाल - भोपाल स्टेशन की मरम्मत और रखरखाव। भाग-बी) भोपाल दिव्यांगजन सुविधाओं में सुधार जैसे कार्य टाइलों का स्पर्शनीय होना ब्रेल साइनेज सहायक बूथ और गैर-प्रकाशित साइनेज। Published cost of tender:** ₹ 4,47,15,956.87. **Earnest Money:** ₹ 3,73,600/-. **Completion Period:** 8 माह। **Last date for submitting tender:** 13.08.2025.

स्वच्छ भारत अभियान - एक कदम स्वच्छता की ओर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)]
(अचल संपत्ति के लिए)
कब्जा सूचना

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 27.08.2017 को एक माँग सूचना जारी कर उधारकर्ता, सह-उधारकताओं और गारंटरों 1. जलगाँव ज्वैलर्स, 2. महेश मंगल, 3. नयनतारा जेम्स एंड ज्वैलरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 4. गोविंद मंगल, 5. श्याम मंगल, 6. राम देवी मंगल को सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया है 4,49,89,757.09/- (रुपये चार करोड़ उनचास लाख नवासी हजार सात सौ सत्तावन और नौ पैसे मात्र) 24.08.2018 को उक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर।

ऋणकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, आज 17 जुलाई 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

ऋणकताओं को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्रभार के अधीन होगा 4,49,89,757.09/- (चार करोड़ उनचास लाख नवासी हजार सात सौ सत्तावन और नौ पैसे मात्र) और उस पर ब्याज।

ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में हैं।

बंधक संपत्ति का विवरण

संपत्ति का संपूर्ण भाग, जिसमें मकान संख्या 08, बड़वाल मस्जिद चौक बाजार, टब्बा मेन रोड, वार्ड संख्या 17, भोपाल, मध्य प्रदेश-462001 शामिल है। पूर्वः श्री किशनलालजी का मकान, पश्चिमः श्री जगन्नाथ का मकान, उत्तरः श्री रामा भाई का मकान और गली, दक्षिणः सरकारी सड़क।

दिनांकः 17-07-2025
स्थानः भोपाल
ऋण खाता संख्याः 1677714

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)